भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3699 का उत्तर

तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाएं

3699. श्री ए. राजा:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच आम बजटों में घोषित की गई परियोजनाओं सहित तमिलनाडु और गुजरात में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) घोषित किए जाने के बावजूद शुरू नहीं की गई रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आबंटित/खर्च की गई निधियों और अप्रयुक्त निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और किसी धनराशि के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं की लागत में और वृद्धि से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/कार्यान्वयन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती

हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्क, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु:

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 तक, पिछले पांच वर्षों में घोषित परियोजनाओं (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) सहित पूर्णत:/अंशत: तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाली 22 रेल परियोजनाएं जिनकी कुल लंबाई 2,587 किलोमीटर है, 33,467 करोड़ रुपये की लागत पर योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 7,153 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	10	872	24	1,223
आमान परिवर्तन	03	748	604	3,267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	09	967	37	2,664
कुल	22	2,587	665	7,153

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रुपए /प्रतिवर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रुपए (7 गुना से अधिक)

यद्यपि निधियों के आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:-

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	3389 हेक्टेयर
भूमि अधिग्रहण	866 हेक्टेयर (26%)
शेष भूमि का अधिग्रहण किया जाना है	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी ला रही है, परंतु इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, कतिपय प्रमुख परियोजनाएं, जो भूमि अधिग्रहण न होने के कारण लंबित हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2	अट्टिपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189

3	मोरप्पुर-धरमापुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4	मन्नारगुड़ी-पट्टुकोट्टई (41 कि.मी.)	152	0	152
5	तंजावुर-पट्टुकोट्टई (52 कि.मी.)	196	0	196

गुजरात:-

गुजरात राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 30,826 करोड़ रुपये लागत की 2,947 कि.मी. कुल लंबाई की 42 रेल परियोजनाएं (6 नई लाइन, 22 आमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) योजना निर्माण और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 826 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 9,336 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इस कार्य की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	6	537	105	3332
आमान परिवर्तन	22	1634	671	4655
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	14	776	50	1349
कुल	42	2947	826	9336

गुजरात राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए वार्षिक बजट आबंटन इस प्रकार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	589 करोड़ रुपये/वर्ष
2024-25	8,743 करोड़ रुपये (लगभग 15 गुना)

गुजरात में महत्वपूर्ण उच्च गति बुलेट गाड़ी परियोजना पर निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। अब 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। गुजरात राज्य में पड़ने वाली इस परियोजना के लगभग 352 कि.मी. खंड में से 225 कि.मी. के लिए वायाडक्ट का निर्माण भी पूरा हो चुका है।

पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा भी गुजरात से होकर गुजरता है। पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा का लगभग 565 मार्ग कि.मी. गुजरात में स्थित है, जो पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 37% है। गुजरात राज्य में पड़ने वाली पूरी परियोजना लंबाई को कमीशन कर दिया गया है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इससे वर्ष, 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****